



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941

No. 112]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

**जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

**मामला सं. (ओ.आई.)04/2019**

**विषय – चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमिनियम एवं जिंक कोटेड फ्लैट प्रोडक्ट्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरुआत अधिसूचना ।**

**फा. सं. 6/4/2019-डीजीटीआर.—**मै. जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से एल्युमिनियम और जिंक के स्टील, प्लेटेड या कोटेड मिश्रण के साथ फ्लैट रोलड उत्पाद के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।

## **विचाराधीन उत्पाद**

2. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी ) है :

"एल्युमिनियम और जिंक के मिश्रण के साथ स्टील, प्लेटेड या कोटेड फ्लैट रोलड उत्पाद । एल्युमिनियम और जिंक के इस मिश्रण में एक या उससे अधिक अतिरिक्त तत्व शामिल हो सकते हैं जिनका अलग-अलग या मिश्रण भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।"

3. पी यू सी क्वायल रूप में या क्वायल रूप में नहीं भी हो सकता है। चाहे प्लेन, कोरोगेटेड या प्रोफाइल रूप में हो अथवा नहीं। पीयूसी टेम्पर मिल पर स्किन पास्ट/प्रोसेस्ड या गैर-स्किन पास्ट हो सकता है, या अतिरिक्त गैर धातु कोटिंग के साथ अथवा बगैर गैर धातु कोटिंग के, बिना सरफेस उपचारित हो अथवा नहीं। पी यू सी को विभिन्न व्यापार नामों जैसे एलू ज़िंक, एएल-जैड एन, ज़िंक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ज़िंक, ज़िंकैल्युम, गेल्वेल्युम आदि के रूप में आपूर्ति किया जा सकता है परंतु ये इन तक ही सीमित नहीं हैं।

4. पी यू सी जंग लगने का प्रतिरोध करता है और इसके प्रयोग में अनेक अनुप्रयोग और क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें अवसंरचना परियोजनाएं, सौर विद्युत परियोजनाएं, रूफिंग, बालिंग, डेकिंग, क्लेडिंग और फ्रेमिंग, व्हाइड गुड्स और अनुप्रयोग, फर्नीचर और कलर कोटेड स्टील के लिए सब-स्ट्रेट शामिल हैं परंतु यह उन तक सीमित नहीं है।

5. पी यू सी में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं :

- i. प्लेट रोलड स्टील उत्पाद जो एल्युमिनियम के बिना ज़िंक से कोटेड हों,
- ii. प्लेट रोलड कलर कोटेड स्टील उत्पाद

6. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मदों 72106100, 72125090, 72259900 और 72269990 के अधीन आता है। पीयूसी का आयात अन्य सीमाशुल्क टैरिफ मदों 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 आदि के अधीन भी आयात किया जा रहा है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

7. समान वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार निम्नलिखित है:-

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

8. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित पी यू सी और संबद्ध देशों से आयातित पी यू सी समान उत्पाद हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित पी यू सी और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित पी यू सी और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अनुसार समान वस्तु माने जाने चाहिए।

9. अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

### घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मै. जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार वे भारत में पी यू सी के प्रमुख उत्पादक हैं, जिनका भारत में कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है या वह संबद्ध देशों से किसी का संबंधित पक्ष नहीं है और वे संबद्ध देशों में पी यू सी के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

11. याचिकाकर्ता के अलावा भारत में पी यू सी के तीन अन्य उत्पादक हैं अर्थात् मै. टाटा ब्लूस्कोप स्टील प्रा. लि., मै. टाटा स्टील बी एस एल लि. और मै. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। तथापि, मै. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड ने 2017 के बाद से पी यू सी का उत्पादन नहीं किया है।

12. अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता जिसके पास वर्तमान में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, नियम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को भी पूरा करता है।

**शामिल देश**

13. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य हैं।

**सामान्य मूल्य**

14. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. और वियतनाम को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन गण तथा वियतनाम के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने भारत में विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर दो देशों के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है।

15. याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि अत्यधिक राजकीय प्रभाव आदि के कारण चीन जन. गण. में इस्पात उद्योग में अत्यधिक बाजार विकृतियां प्रचलित हैं। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए तब तक चीन जन. गण. में प्रचलित लागतों और कीमतों को स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया है जब तक चीन जन. गण. में उत्पादक/निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम न हों कि उनकी लागत और कीमतें विकृत नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि यूरोपीय आयोग ने अपनी हाल की प्रकाशित रिपोर्ट में चीन जन. गण. के विशिष्ट क्षेत्रों में मौजूद बाजार विकृतियों की जांच की है और यह पाया है कि चीन जन.गण में भूमि, ऊर्जा, पूंजी, कच्ची सामग्रियों और श्रम से संबंधित देशव्यापी बाजार विकृतियां मौजूद हैं।

16. तदनुसार, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, चीन जन.गण. और वियतनाम में उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, चीन जन.गण. और वियतनाम से उत्पादक/निर्यातक को निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट करना होगा और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करानी होगी:

(क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

(ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

(ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

(घ) विनिर्माण दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

17. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन कोरिया गणराज्य में प्रचलित हॉट रोलड क्वाइल की घरेलू कीमत और अन्य कच्ची सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत और भारत में आवेदक द्वारा वहन किए गए अन्य खर्चों को तर्कसंगत लाभ के लिए समायोजित करके किया है। अतः प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा यथा परिकलित सामान्य मूल्य पर भरोसा करने का निर्णय लिया है।

**निर्यात कीमत**

18. आवेदक ने (डी जी सी आई एंड एस,) कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत परिकलित की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और पत्तन संभलाई खर्चों, अंतरदेशीय भाड़ा, बैंक प्रभारों, कमीशन/व्यापारी का लाभ और गैर-वापसी योग्य वैट (केवल चीन जन. गण. के मामले में) के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई शुद्ध निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

**पाटन मार्जिन**

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

### **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

20. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप समग्र रूप से पाटित आयातों की भारी मात्रा और भारत में उत्पादन और पाटन के संबंध में, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है जो पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराता है।

### **पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

21. और जबकि प्राधिकारी प्रथम दृष्टया पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **जांच की अवधि**

22. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अक्टूबर, 2017 से 30 सितंबर, 2018 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 से मार्च 2018 और जांच अवधि की अवधियां भी शामिल होंगी।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

23. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा गया है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जाएं :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**

**वाणिज्य विभाग**

**भारत सरकार**

**चौथा तल , जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**

**नई दिल्ली- 110001**

25. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

### **समय-सीमा**

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली

के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा :

- i. गोपनीय रूप में अंकित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची आदि सहित), और
- ii. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची आदि सहित)

29. गोपनीय या अगोपनीय अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना संभव न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

35. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2019

**Case No. (O.I.) 04/2019**

**Subject: Initiation of Anti-dumping investigation on the imports of “Aluminium and Zinc coated flat products” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.**

**F. No. 6/4/2019-DGTR.**—M/s. JSW Steel coated Products Limited, (hereinafter referred to as “petitioner/Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminum and Zinc, from China PR, Vietnam and Korea RP (hereinafter also referred to as the ‘subject countries’).

**Product under consideration**

2. The product under consideration (PUC) for the purpose of present investigation is :

*“Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight.”*

3. The PUC may be in coil form or not in coil form whether or not plain, corrugated or in profiled form. The PUC may be skin-passed / processed on temper-mill or non-skin-passed whether or not surface treated with or without additional non-metallic coating. PUC may be supplied in various trade names including but not limited to Alu-Zinc, Al-Zn, Zinc Aluminum, Aluminum Zinc, Zinalume, Galvalume etc.
4. The PUC offers resistance to corrosion, and is used in many applications and sectors including but not limited to infrastructure projects, solar power projects, roofing, walling decking, cladding and framing, white goods and appliances, furniture and substrate for colour coated steel.
5. PUC does not include the following products: -
- Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium;
  - Flat rolled color coated steel products
6. The PUC falls under tariff items 72106100, 72125090, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is also being imported under other Customs Tariff Items 72101290, 72103090, 72104900, 72106900, 72107000, 72109090, 72121090, 72122090, 72123090, 72124000, 72169910, 72255010, 72259100, 72259200, 72269930 etc. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

**Like Article**

7. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

8. The petitioner has submitted that the PUC produced by the petitioner company and the PUC imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the PUC exported from subject countries and that produced by the petitioner. PUC produced by the petitioner and imported from subject countries is comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can

use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

9. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as 'Like Article' within the meaning of the Rule 2 (d) to the subject goods being imported from the subject countries.

#### **Domestic Industry & standing**

10. The Application has been filed by M/s JSW Steel Coated Products Limited, as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the major producer of the PUC in India, account for more than 60% of the total production in India. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject countries and they are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
11. Apart from the petitioner, there are three other producers of the PUC in India, namely, M/s. Tata BlueScope Steel Private Limited, M/s. Tata Steel BSL Limited and M/s. Asian Colour Coated Ispat Limited. M/s. However, M/s. Asian Colour Coated Ispat Limited has not produced the PUC from 2017 onwards.
12. The Authority, therefore, determines that the petitioner who presently holds a "major proportion" of the total domestic production, constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

#### **Countries involved**

13. The countries involved in the present investigation are China PR, Vietnam and Korea RP.

#### **Normal Value**

14. The petitioner has claimed that China PR and Vietnam should be treated as a non-market economy countries and normal value in case of China PR and Vietnam should be determined in accordance with para-7 of Annexure I of the Rules. The petitioner has claimed normal value for the two countries on the basis of cost of production in India, duly adjusted.
15. The Petitioner has also submitted that there are significant market distortions prevailing in the steel industry in China PR due to significant state influence, etc. The petitioner has requested the Authority not to accept the costs and prices prevailing in China PR for determining the normal value unless producers/ exporters in China PR are able to demonstrate that their costs and prices are not distorted. The Petitioner has also submitted that European Commission in its recently published report has examined the market distortions that exist in specific sectors in China PR and has found that there exists countrywide market distortions related to land, energy, capital, raw materials and labour in China PR.
16. Accordingly, while submitting the questionnaire response producers/exporters from China PR and Vietnam have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacturing, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter from China PR and Vietnam, may clarify and provide sufficient information on the following:
  - a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
  - b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
  - c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
  - d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.
17. Further, the petitioner has constructed the normal value for Korea RP based on the domestic price of Hot Rolled Coil prevailing in Korea RP and other raw material cost, conversion cost and other expenses as incurred by the Applicant in India duly adjusted for reasonable profit. The Authority has,

therefore, for the purpose of the initiation, decides to proceed with the normal value as constructed by the petitioner.

**Export Price**

18. The applicant has computed the export price on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance and port handling expenses, inland freight, bank charges, commission/traders profit, and non-refundable VAT (in case of China PR only). There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the petitioners.

**Dumping Margin**

19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

**Injury and Causal Link**

20. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling, capacity utilization, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

**Initiation of Anti-Dumping investigations**

21. And whereas the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry

**Period of Investigation**

22. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1<sup>st</sup> October 2017 to 30<sup>th</sup> September 2018. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

**Submission of information**

23. The known exporters in the subject countries and their Government through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Trade Remedies,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,  
New Delhi-110001**



25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

26. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

**Submission of information on confidential basis**

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

35. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority